

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्ली: आश्विन02, 1944

शनिवार: 24सितंबर 2022

रक्षा लेखा विभाग के 275वें वार्षिक दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री द्वारा शुरू की गई प्रमुख डिजिटल पहलों में अग्निवीरों के लिए वेतन प्रणाली और स्पर्श मोबाइल ऐप शामिल

“हमारा प्रयास सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ-साथ उनके परिवारों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना है”

पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए: श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) से कहा

शक्तिशाली सेना और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है: त्वरित निर्णय युद्ध की तैयारियों को मजबूत करते हैं: रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 01 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के 275 वें वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) (स्पर्श) मोबाइल ऐप; अग्निवीरों के लिए वेतन प्रणाली; रक्षा यात्रा प्रणाली (डीटीएस) में अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट बुकिंग मॉड्यूल; रक्षा लेखा प्राप्तियां और भुगतान प्रणाली (दर्पण); रक्षा सिविलियन वेतन प्रणाली और रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में सरकार के 'डिजिटल इंडिया' की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा लेखा विभाग की सराहना करते हुए कहा कि नई पहलों से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख विभागीय परियोजनाओं- स्पर्श का विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन में अनुकरणीय पहल प्रदर्शित करने के लिए तीन टीमों को उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। इन टीमों में डीआरडीओ में ई-सहमति का कार्यान्वयन और वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) भारती: आपका पीएओ, चौबीस घंटे एक कॉल दूर शामिल हैं।

स्पर्श मोबाइल ऐप

यह ऐप पेंशनभोगियों के मोबाइल के माध्यम से स्पर्श पोर्टल की महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों के साथ-साथ रक्षा

सिविलियन के लिए रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पोर्टल (<https://sparsh.defencepension.gov.in/>) कार्यान्वित किया। यह दावा शुरू करने से लेकर संवितरण तक सभी पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं का संपूर्ण समाधान है। पेंशनभोगी पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और अपने पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल कर सकते हैं।

'स्पर्श' को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सैनिकों को जीवन पर्यंत तथा मृत्यु के बाद, सेवारत कार्मिकों, पूर्वसैनिकों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही पेंशन वितरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग से पेंशनभोगियों की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटान को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने समस्याओं के मौके पर ही निवारण के लिए नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम और 'रक्षा पेंशन समाधान' संचालित करने के लिए विभाग की प्रशंसा की और उनसे इस दिशा में काम करना जारी रखने का आग्रह किया।

अग्निवीरवेतन प्रणाली

यह प्रणाली अग्निवीरों के लिए कुशल वेतन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी, जो जल्द ही सरकार की परिवर्तनकारी अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में शामिल होंगे। पूरी तरह से स्वचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली अग्निवीरों के दावा प्रसंस्करण और वेतन सूची/पे-रोल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष और सुरक्षित पोर्टल होगा। श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में अग्निवीरों के लिए एक केंद्रीकृत पीएओ (सेना) का भी उद्घाटन किया।

डिफेंस ट्रेवल सिस्टम

यह प्रणाली रेल और हवाई टिकटों की बुकिंग से लेकर कैशलेस और पेपरलेस वातावरण में रक्षा सेवाओं और सिविलियनों के लिए अपने पोर्टल पर दावेका अनुरोध करने तक संपूर्ण समाधान प्रदान करती है। यह एयर एक्सचेंज वारंट की जगह रक्षा सेवाओं के लिए विदेश यात्रा के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगी। यह जीएसएल रसीद और टिकट बुकिंग के बीच लगने वाले समय को कम करेगा और यात्रा अधिकारी की परेशानी को समाप्त करेगा।

दर्पण

रक्षा लेखा प्राप्तियां और भुगतान प्रणाली तीसरे पक्ष के बिल भुगतान और लेखांकन के लिए एक एकीकृत समाधान है। इसकासही समय पर प्रसंस्करण विभिन्न लेखाकरण और वित्तीय प्रदर्शनों में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा।

रक्षा वेतन सिविलियन प्रणाली

इस प्रणाली में एकल, केंद्रीकृत और पूर्णतः स्वचालित प्रणाली के माध्यम से सभी रक्षा सिविलियनों के वेतन के संवितरण की परिकल्पना की गई है। यूनिटों और पीसीडीए/ सीडीएदोनों

कार्यालयों को सिस्टम तक पहुंच प्रदान की गई है और यूनितें पोर्टल पर ही भुगतान की स्थिति की जांच कर सकेंगी।

रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

अनुप्रयोग के शुभारंभ के साथ, विभाग डिजिटल रूप से सक्षम मानव संसाधन प्रबंधन के एक नए प्रतिमान में कदम रखता है। प्लेटफॉर्म में ई-सर्विस बुक, अवकाश प्रबंधन, वतन-सूची तैयार करना/पे रोल जनरेशन और पदोन्ति ब्योरे जैसे विभिन्न सेल्फ-सर्विस मॉड्यूल हैं जो मोबाइल ऐप के माध्यम से कर्मचारियों के लिए, कहीं भी, कहीं भी सुलभ होंगे।

पीएओ-भारती

इस पहल के माध्यम से, जो इस वर्ष रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों का हिस्सा था, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक वेतन एवं भत्तों और दावों से संबंधित सटीक डेटा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, इसके इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से, कार्मिकटेलीफोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और 48 घंटे के भीतर जवाब प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली सात वेतन एवं लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित की गई है। रक्षा मंत्री ने आशा व्यक्त की कि इसे जल्द ही शेष कार्यालयों में भी कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह ने इन डिजिटल पहलों को अपनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के मंत्र को आत्मसात करने के लिए रक्षा लेखा विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा, "विभाग पारंपरिक मूल्यों से जुड़े रहते हुए बदलते समय के अनुसार खुद को विकसित कर रहा है।"

रक्षा मंत्री ने वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन करते हुए सेवाओं के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में रक्षा लेखा विभाग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "जैसा कि भारत ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह 2047 तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनने के लिए 'अमृत काल' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत के पास एक मजबूत सेना हो, जो अत्याधुनिक हथियारों/उपकरणों से लैस हो, जो 'आत्मनिर्भर' रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित हो। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना शुरू से ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित करना उस अटूट संकल्प का प्रमाण है। रक्षा लेखा विभाग इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' की परिकल्पना को साकार करने में विभाग द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रक्षा लेखा विभाग को त्वरित निर्णयों के माध्यम से सरकार के प्रयासों के

प्रति अपना समर्थन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देरी से न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि देश की समाघात तत्परता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।”

रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं के प्रदर्शन और दक्षता ऑडिट के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह समिति ऑडिट के माध्यम से मंत्रालय में किए जा रहे कार्यों की नए और रचनात्मक दृष्टिकोण से समीक्षा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि रक्षा लेखा विभाग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे न केवल सेवाओं की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि फिजूलखर्ची में भी कमी आएगी।

श्री राजनाथ सिंह ने वित्तीय सलाह दी; रक्षा मंत्रालय में रक्षा लेखा विभाग की तीन प्रमुख भूमिकाओं के रूप में लेखाकरण, बिल बनाना/भेजना और भुगतान तथा आंतरिक लेखा परीक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने विभाग को नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हुए वित्तीय सलाह और बिलिंग तथा भुगतान पर एक फेसलेस प्रणाली स्थापित करने के अवसरों का पता लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विभाग इसी उत्साह और समर्पण के साथ अपने विभागीय कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखेगा और देश के रक्षा वित्तीय प्रबंधन में योगदान देगा।

इस अवसर पर रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) श्रीमती रसिका चौबे, रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) श्री अविनाश दीक्षित और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एबीबी/डीएस